नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी
1934 से

रथ पर निकले जगत के नाथ

10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

09 दिन तक रहने के बाद फिर आते हैं वापस

भुवनेश्वर, 16 जुलाई. ओडिशा की तीर्थ नगरी जगन्नाथ पुरी में 10 लाख श्रद्धालु गुरुवार को देश के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक त्योहारों में से एक भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा देखने के लिए जमा हुए. ओडिशा के पुरी शहर का अद्भुत नजारा पूरा विश्व देख रहा है.

लाखों श्रद्धालुओं का विशाल जन-सैलाब, आसमान छूते भव्य रथ और एक ऐसी परंपरा जहां ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह की सीमाओं को छोड़कर अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं. ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि जीता-जागता इतिहास है.

> **इतिहास पौराणिक कथा**
> ऐतिहासिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने एक बार अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाने की इच्छा जताई। उसी याद में हर साल उन्हें रथ पर बिठाकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ये 9 दिन तक वहां रहते हैं और फिर वापस आते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं.

> **पुरी रथयात्रा में भगदड़ से एक की मौत**
> भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान गुरुवार को भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में एक श्रद्धालु की मौत हो गई. वहीं, करीब 200 लोग घायल हैं. जिस श्रद्धालु की मौत हुई है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

परिसीमन का विरोध करेगी कांग्रेस

- सोनिया गांधी के आवास पर हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक
- खरगे ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

नई दिल्ली, 16 जुलाई। संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की नेता सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

बैठक में संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों, सरकार की विभिन्न जनहित और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर घेरने की रणनीति तथा विपक्ष के साथ समन्वय जैसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में श्रीमती गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, सांसद मनीष तिवारी तथा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

> **खरगे ने मोदी को लिखा पत्र**
> लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या बढ़ाने का विधेयक संसद में फिर लाए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खरगे ने गुरुवार को लिखे इस पत्र में कहा है कि उन्होंने मार्च और अप्रैल में किरण रिजिजू को पत्र लिखकर अनुरोध किया था लेकिन उनका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला था.

5 राज्यों के 13 ठिकानों पर रेड

- विदेशी फंडिंग नेटवर्क ठिकानों पर रेड
- दिल्ली से बंगाल तक ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी

नई दिल्ली, 16 जुलाई. प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत प्राप्त धनराशि के कथित दुरुपयोग और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को पांच राज्यों में 13 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया.

यह कार्रवाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में की गई. जांच उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई है.

ईडी के जांच में ऐसे कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं सामने आई हैं, जिन्हें विदेश से एफसीआरए के तहत धन प्राप्त हुआ. एजेंसी का आरोप है कि इस धन का इस्तेमाल विभिन्न बैंक खातों और कई स्तरों वाले वित्तीय लेनदेन के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया गया. जांच में छोटे-छोटे भुगतान, जैसे 6 हजार, 8 हजार और 10 हजार रुपये की किश्तों में धनराशि भेजे जाने के पैटर्न की भी जानकारी मिली है. जांच के दौरान ऐसे नेटवर्क के संकेत मिले हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कराने और विभिन्न राज्यों में उन्हें बसाने से जुड़ा हो सकता है.

वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर सरकार सख्त

महत्वपूर्ण मिशनों के वैज्ञानिकों का इस्तीफा अब सीधे नहीं होगा मंजूर

नई दिल्ली, 16 जुलाई. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के गगनयान, चंद्रयान और अन्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के 100 से अधिक इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है.

अंतरिक्ष विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस) द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के इस्तीफे अथवा वीआरएस संबंधी मामलों का अंतिम निर्णय अब सीधे विभाग स्तर पर लिया जाएगा. अंतरिक्ष विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि हाल के समय में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के संचालन और समयबद्ध प्रगति पर प्रभाव पड़ने की आशंका है. इसी कारण यह नई प्रक्रिया लागू की गई है ताकि महत्वपूर्ण मिशनों में कार्यरत विशेषज्ञों की उपलब्धता बनी रहे.

> हालांकि, इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इससे परियोजनाओं को अचानक होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा. वैज्ञानिकों के इस्तीफे रोकने के लिए 14 जुलाई को एक नया अंदरूनी फरमान जारी किया है. इंटरनल मेमोरेंडम में कहा गया है कि हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स से जुड़े ग्रुप ए के साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के अनुरोधों को अब रूटीन के तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा।